

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया ने किया सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अर्थशास्त्र विभाग ने 6-7 मार्च 2024 के दौरान सतत विकास लक्ष्य: प्रगति, चुनौतियां और आगे की रणनीति पर वैश्विक कॉन्क्लेव का आयोजन किया। कॉन्क्लेव की शुरुआत अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अशरफ इलियान की स्वागत टिप्पणी के साथ हुई। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व निदेशक प्रोफेसर पार्थ सेन ने अध्यक्षीय भाषण दिया।

प्रो. सेन ने सरकार के परस्पर विरोधी उद्देश्यों पर जोर दिया, यानी, एक तरफ सरकारें सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल करना चाहती हैं और दूसरी तरफ सरकारों को राजकोषीय और मौद्रिक संतुलन हासिल करने की भी जरूरत है। जबकि एसडीजी की प्राप्ति में सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा इत्यादि जैसे स्टॉक चर का एक निश्चित न्यूनतम स्तर प्राप्त करना शामिल है जो अर्थव्यवस्था के निरंतर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालाँकि, हर लगातार अवधि में राजकोषीय और मौद्रिक संतुलन हासिल करने की आवश्यकता सरकार को खर्च और ऋण में कटौती करने के लिए मजबूर करती है। जबकि ग्लोबल नॉर्थ ने अपने स्टॉक वेरिबल्स की समस्या को बड़े पैमाने पर हल कर लिया है और विशेष रूप से प्रवाह वेरिबल्स के मैक्रो संतुलन के प्रबंधन के बारे में चिंतित है, ग्लोबल साउथ अपने स्टॉक वेरिबल्स में सुधार के लिए संघर्ष कर रहा है जो मोटे तौर पर मानव विकास संकेतकों द्वारा कैप्चर किए गए हैं।

एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएन-ईएससीएपी), दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया कार्यालय के उप प्रमुख और वरिष्ठ आर्थिक मामलों के अधिकारी डॉ. राजन सुदेश रत्न ने अपने उद्घाटन भाषण में इस बात की सराहना की कि एसडीजी और दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति और संगठन की जिम्मेदारी प्रासंगिक हैं। उन्होंने दोहराया कि हम यूएन-ईएससीएपी रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र में 89% संकेतकों के लक्ष्य हासिल करने से बहुत दूर हैं। एसडीजी की उपलब्धि में देशों के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करते हुए, उन्होंने सरकारों को साक्ष्य-आधारित नीतिगत हस्तक्षेप करने में मदद करने में शोधकर्ताओं की भूमिका पर जोर दिया।

श्री उचिता डी जोयसा, अध्यक्ष, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस (जीएलओएसएस), कार्यकारी निदेशक, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एम्प; डेवलपमेंट (सीईडी), कोलंबो, श्रीलंका ने कहा कि धीमी और असंतोषजनक प्रगति के बावजूद, एसडीजी के पीछे मूल विचार वैश्विक चुनौतियों के बारे में सोचने के मामले में दुनिया को बदलना है, न कि केवल देशों द्वारा लक्ष्य हासिल करना।

उद्घाटन सत्र के बाद, पहला पूर्ण सत्र प्रतिष्ठित वक्ताओं जैसे प्रो. अचिन चक्रवर्ती, पूर्व निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज कोलकाता, प्रो. संतोष मेहरोत्रा, पूर्व अध्यक्ष, सेंटर फॉर इनफॉर्मल सेक्टर एंड लेबर स्टडीज, जेएनयू, नई दिल्ली और विजिटिंग प्रोफेसर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ, यूके, प्रोफेसर कविता राव, निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) और डॉ. तौहिदुर रहमान, संस्थापक निदेशक, इनिशिएटिव फॉर एजेंसी एंड डेवलपमेंट (आईएफएडी) और एसोसिएट प्रोफेसर, कृषि और संसाधन

अर्थशास्त्र विभाग, एरिज़ोना विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के साथ शुरू हुआ। प्रोफेसर अचिन ने एसडीजी से संबंधित लक्ष्य संकेतकों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए पेशेवर आर्थिक सिद्धांत में नवीनतम प्रगति का उपयोग करने पर जोर दिया। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा ने तर्क देते हुए सुसंगत कहानी बुनी कि यदि मानव विकास आर्थिक विकास से पहले होता है तो हमें गरीबी और असमानता पर एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना है। प्रोफेसर कविता राव ने एसडीजी के लिए प्रासंगिक खर्च की एक समान परिभाषा और माप प्राप्त करने में कठिनाई को रेखांकित किया। डॉ. तौहिदुर रहमान ने एसडीजी की उपलब्धि में लैंगिक आयामों को तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया। उन्होंने तर्क दिया कि भारत में महिला श्रम बल भागीदारी में प्रगति की कमी मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि हम उन लिंग मानदंडों को संबोधित करने में सक्षम नहीं हैं जो महिलाओं की स्वायत्तता और एजेंसी में बाधा डालते हैं।

सम्मेलन के दूसरे पूर्ण सत्र की अध्यक्षता जेएनयू के प्रो. प्रवीण झा ने की। प्रोफेसर अरुण कुमार, पूर्व प्रोफेसर, जेएनयू, प्रोफेसर जॉयश्री रॉय, निदेशक-स्मार्ट सेंटर, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एआईटी), थाईलैंड। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च (आईजीआईडीआर) के प्रोफेसर श्रीजीत मिश्रा सत्र में वक्ता थे। सत्र का फोकस स्थिरता में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर था। प्रोफेसर अरुण कुमार ने वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति की ओर संकेत किया जो सतत विकास के लिए एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करती है। इसी तरह, प्रो. श्रीजीत मिश्रा ने करंट साइंस ग्लोबल रिएक्शन टू सीओवीआईडी में अपने हालिया प्रकाशन से साक्ष्य का उपयोग करते हुए कहा कि सीओवीआईडी जैसे वैश्विक पॉली संकटों की प्रतिक्रिया में ठोस साक्ष्य आधार होना चाहिए और संकट के लिए आनुपातिक होना चाहिए।

प्रो. जॉयश्री की प्रस्तुति में भारत के मेट्रो शहरों में परिवेश के तापमान और आर्द्रता को देखते हुए मैनुअल श्रमिकों के लिए व्यावहारिकता की जांच करने की कोशिश की गई। उन्होंने पाया कि एयर कंडीशनिंग जैसे चरम समाधानों तक किसी भी वर्ष में 90% से अधिक दिन गैर-कार्य योग्य क्षेत्र में रहते हैं।

कॉन्क्लेव का तीसरा पूर्ण सत्र फिर से हमारे समय के अत्यधिक प्रतिष्ठित विद्वानों से खचाखच भरा हुआ था। प्रोफेसर एस महेंद्र देव, वर्तमान में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली (ईपीडब्ल्यू) के संपादक और इंदिरा गांधी और विकास अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक और कुलपति ने सत्र की अध्यक्षता की। प्रोफेसर नानक काकवानी, पूर्व प्रमुख, अर्थशास्त्र विभाग, साउथ वेल्स विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया, प्रोफेसर गौरव दत्त, मोनाश विश्वविद्यालय और प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, पूर्व डीन, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जेएनयू सत्र में वक्ता थे। प्रो. काकवानी ने बताया कि हालांकि एसडीजी के लिए 169 लक्ष्य संकेतक हैं, हमारे पास सभी देशों के लिए उन सभी को ट्रैक करने के लिए सीमित डेटा है। ऐसे सारांश उपाय करना उपयोगी है जो यह आकलन कर सकें कि कोई समाज समग्र रूप से कैसा प्रदर्शन कर रहा है।

उन्होंने समावेशी विकास, समावेशी विकास, गरीब-समर्थक विकास और गरीब-समर्थक विकास नामक चार उपाय प्रस्तावित किए। प्रो. अमिताभ कुंडू ने तर्क दिया कि किसी निश्चित समय पर गरीबी का आकलन उपभोग के साथ-साथ बहुआयामी गरीबी का उपयोग करके किया जाना चाहिए। किसी एक पर विशेष रूप से निर्भर रहने से अंधे धब्बे पैदा हो सकते हैं जिससे नीति निर्माताओं के लिए गरीबी के विभिन्न आयामों को संबोधित करना कठिन हो जाएगा। प्रोफेसर गौरव दत्त ने 70 के दशक की

शुरुआत से गरीबी के विकास का पता लगाया। उन्होंने पहचाना कि 1990 के दशक के दौरान गरीबी में गिरावट तेज हो गई। उन्होंने खपत की माप में कई डेटा गैप्स पर भी प्रकाश डाला।

तीन पूर्ण सत्रों के अलावा कॉन्क्लेव में 14 तकनीकी सत्र शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक सत्र में औसतन 5 पेपर थे, कुल मिलाकर 70 से अधिक पेपर थे। प्रस्तुत पत्रों में आवर्ती विषय स्थानीय पर्यावरण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियाँ, सभ्य रोजगार सृजन में चुनौतियाँ, गरीबी और पोषण और विशिष्ट जनसंख्या समूहों द्वारा सामना किए जाने वाले स्वास्थ्य मुद्दे थे।

समापन समारोह में डॉ. जकारिया सिद्दीकी, एसोसिएट प्रोफेसर एवं डॉ. जामिया के अर्थशास्त्र विभाग के सम्मेलन संयोजक ने रिपोर्टर्स रिपोर्ट का एक संक्षिप्त संस्करण प्रस्तुत किया, जिसके बाद प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव, पूर्व प्रोफेसर, सीएसआरडी, जेएनयू ने समापन भाषण दिया। उन्होंने सम्मेलन के दो दिनों के दौरान विचार-विमर्श के महत्व पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से एसडीजी की प्रगति का आकलन करने में पेशेवर अर्थशास्त्र के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया। प्रोफेसर अब्दुल शाबान अध्यक्ष, सीपीपीएचएचडी, टीआईएसएस, मुंबई ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई और कॉन्क्लेव के प्रमुख क्षणों को दोहराया। उन्होंने एसडीजी में प्रगति का आकलन करने में डेटा और माप संबंधी मुद्दों पर विशेष रूप से जोर दिया।

सतत विकास के लिए राष्ट्रीय अभियान के कार्यकारी निदेशक, श्री दया सागर श्रेष्ठ ने सम्मेलन में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रयास करने के लिए अर्थशास्त्र विभाग को बधाई दी। उन्होंने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि नागरिक समाज और शैक्षणिक संस्थानों के बीच आदान-प्रदान ज्ञान वृद्धि के एक अच्छे चक्र को बढ़ावा दे सकता है। इस कार्यक्रम का व्यवस्थित समन्वय जेएमआई के अर्थशास्त्र विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. मोहम्मद काशिफ खान द्वारा किया गया। कॉन्क्लेव का समापन जेएमआई के अर्थशास्त्र विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. वसीम अकरम द्वारा दिए गए धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

जनसंपर्क कार्यालय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया